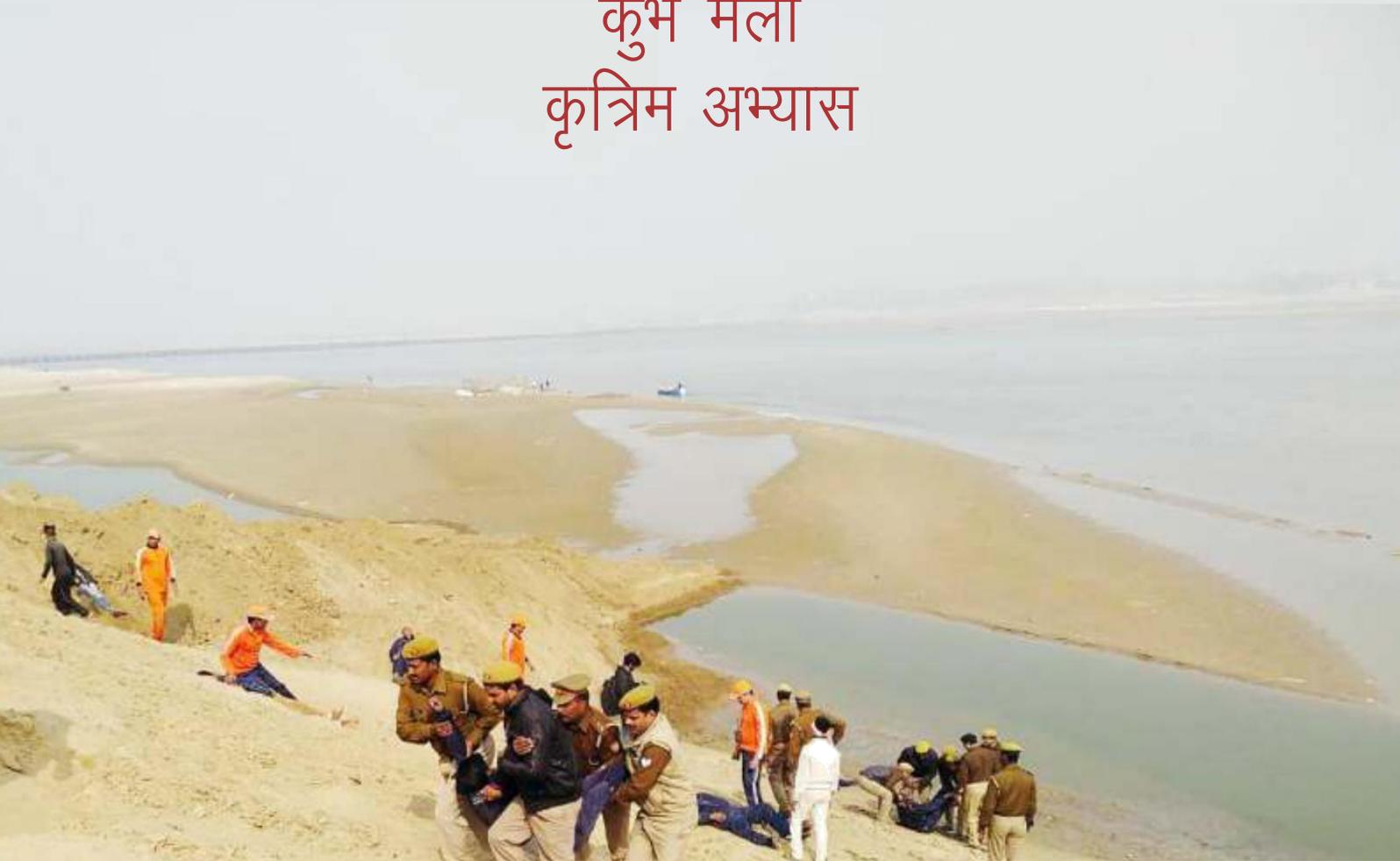


जनवरी, 2019



आपदा संवाद

कुंभ मेला कृत्रिम अभ्यास



3



भारत-जापान
सहयोग



9

14वां
स्थापना दिवस



सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की 8वीं बटालियन ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इस वर्ष प्राप्त किया। पुरस्कार की घोषणा 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि पर की गई। पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र तथा 51 लाख रुपए की एक नकद इनाम राशि शामिल है। 2006 में स्थापित, यह बटालियन एक अति-विशिष्ट बचाव तथा मोचन बल है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर भारत-जापान सहयोग

भारत और जापान, ये दो देश संसार में सर्वाधिक आपदा प्रवण देशों में शामिल हैं। जापान पेसिफिक रिंग ऑफ फायर के साथ स्थित है और भूकंपों के प्रति अतिसंवेदनशील है। विनाशकारी भूकंपों के लंबे इतिहास के साथ, जापान में सामुदायिक जागरूकता का एक अति-उच्च स्तर है। अपने प्रौद्योगिकीय ज्ञान के साथ यह देश, विशेष रूप से भूकंप जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में, संसार में सबसे अधिक उन्नत देशों में से एक है।

भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है और आधारढाचा क्षेत्र में एक भारी निवेश सन्निकट है। चूंकि भारत की भूमि का करीबन 59% सामान्य से लेकर विकट भूकंपों के प्रति प्रवण है, इसलिए किसी भूकंप की स्थिति में यह सहयोग न केवल लोगों की जाने बचाएगा बल्कि बड़े आर्थिक समझ को भी तैयार करता है कि इस धन राशि का निवेश भूकंप समुत्थानशीलता के लिए किया गया है।

एक आपदा-समुत्थानशील एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, यह अनिवार्य है कि भारत और जापान आपदा जोखिम के समाधान के लिए एक साथ आए। इस दिशा में, दोनों देशों ने, आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) में सहयोग के क्षेत्रों पर एक विशिष्ट द्विपक्षीय कार्य-योजना विकसित करने के उद्देश्य के साथ, सितंबर, 2017 में डीआरआर पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद 14 मार्च, 2018 को नई दिल्ली में डीआरआर पर पहली भारत-जापान कार्यशाला आयोजित की गई।

ऊपर उल्लिखित कार्यशाला के निष्कर्षों के आधार पर, विशेष विषयगत क्षेत्रों पर दूसरी भारत-जापान कार्यशाला का 15 अक्टूबर, 2018 को टोकियो में आयोजन किया गया। डॉ. पी.के. मिश्रा, माननीय प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव की अगुवाई में एक भारतीय शिष्ट मंडल ने इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए 12 से 16 अक्टूबर, 2018 तक जापान की यात्रा की।

12-सदस्यीय शिष्टमंडल जिसमें केंद्र सरकार, पांच राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ देश के शीर्ष तकनीकी संस्थानों से वैज्ञानिक तथा अनुसंधानकर्ता शामिल थे, ने अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस पर एक विशेष सत्र में भी भाग लिया।



शिष्टमंडल ने उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय बैठकों का भी आयोजन किया और दो स्थानों—कावासाकी और कटोरी—में भी गया जहां शहरी बाढ़ नियंत्रण आधारदांचा तैयार किया गया था।

कार्यशाला के उद्घाटन समारोह के दौरान, दोनों देशों ने निकट संबंधों के व्यापक संदर्भ के अंतर्गत डीआरआर के क्षेत्र में लगातार सहयोग और दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग की आवश्यकता को पुनः पुष्ट किया। डीआरआर पर दोनों देशों के बीच एक निरंतर संवाद को बढ़ाने और पारस्परिक आदान-प्रदान की दिशा में कार्यशाला को एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए, डॉ. मिश्रा ने कहा की अब तक की गई प्रगति के बावजूद, हाल की घटनाओं ने संकेत दिया है कि हम आत्मसंतुष्ट होना वहन नहीं कर सकते हैं।

डीआरआर पर तीसरी भारत-जापान कार्यशाला का मार्च, 2019 में नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा।

जापान के पक्ष को इस महत्वपूर्ण कार्यशाला को आयोजित करने के लिए धन्यवाद देते हुए श्री सुजन चुनौई, जापान में भारत के राजदूत ने कहा नीचे, "हम क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर लोगों की जान बचाने तथा आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। अभी काफी कुछ बाकी है जो वैश्विक सहमति बना कर और सहयोग के द्वारा सभी असुरक्षित देशों में नुकसान के प्रशमन के लिए किया जा सकता है। हमारे साझा मूल्यों तथा बढ़ते मेल-मिलाप के साथ, भारत और जापान आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई रूपरेखा द्वारा दिखाए जा रहे रास्ते के साथ इस बारे में एक दूसरे के प्रयासों में मदद कर सकते हैं।"

यह कार्यशाला चार मुख्य विषयों के इर्द-गिर्द केंद्रित थी : 1) कृत्रिम कवायद, अभ्यास तथा प्रशिक्षण; 2) मौसमी खतरों; 3) भूकंप की पूर्व जांच तथा चेतावनी प्रणालियां तथा 4) आपदा जोखिम प्रबंधन में उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग।

13 अक्टूबर, 2018 को डीआरआर को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस पर जापान के राष्ट्रीय सम्मेलन पर विशेष सत्र में, डॉ. मिश्रा ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी पहलुओं पर निगम के अलावा स्थानीय

आत्म-विश्वास को बढ़ाने के अनुभव को सांझा करने के महत्व को रेखांकित किया।

इन विचार-विमर्शों ने भूकंप जोखिम आंकलन तथा शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन पर विशेष फोकस के साथ, दो देशों के वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्थानों के बीच एक गहरे रिश्ते के लिए मंच स्थापित किया है। •



मंत्रिमंडल कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ बैठक

आने वाले सालों में दो देशों के बीच और अधिक सहयोग बढ़ाने के लिए भी डॉ. पी.के. मिश्रा ने दो द्विपक्षीय बैठकों की अगुवाई की – एक श्री जुंजो यामामोटो, आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री, मंत्रिमंडल कार्यालय, जापान और दूसरी श्री हिरोतो इजुमी, माननीय प्रधानमंत्री, जापान के विशेष सलाहकार के साथ।

जापान में भारत के राजदूत श्री सुजन चिनौई, श्री कमल किशोर, सदस्य, एनडीएमए; सुश्री रजनी सेकरी सिब्ल, अपर सचिव, आपदा प्रबंधन, गृह मंत्रालय और मिशन के डिप्टी चीफ (जापान में भारत का दूतावास) श्री राज श्रीवास्तव इन बैठकों में उपस्थित हुए।

डॉ. मिश्रा ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण मुद्दों पर जापान के वैश्विक नेतृत्व के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने आपदा समुत्थानशील आधारदांचा पर फोकस करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया और आपदा समुत्थानशील आधारदांचा पर गठबंधन के लिए जापान की सहायता मांगी।

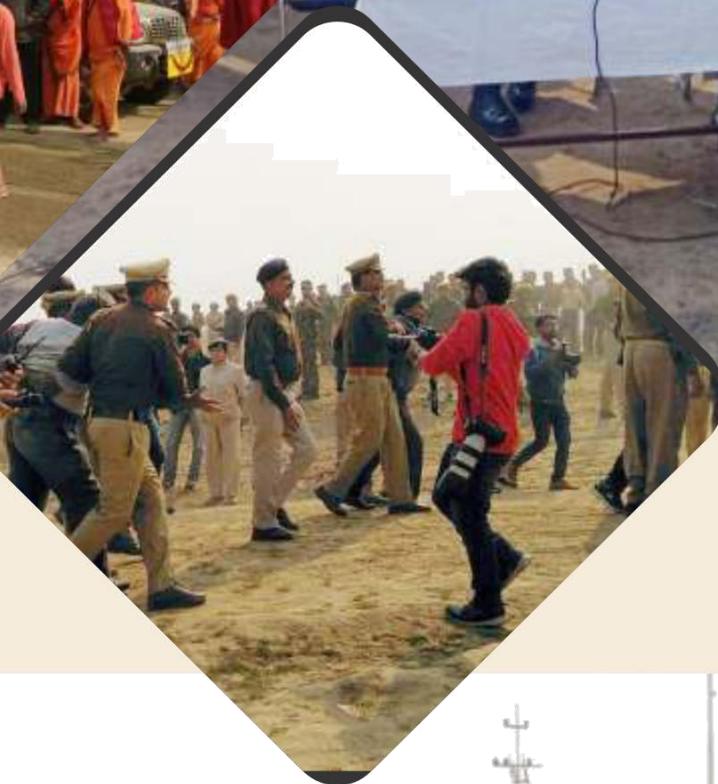
कुंभ मेला कृत्रिम अभ्यास



कुंभ मेला 2019 जो संसार में लगने वाला सबसे बड़े जन-समूह एकत्रण वाला तथा आस्था के सामूहिक कृत्य से जुड़ा एक मेला है, 15 जनवरी से 04 मार्च, 2019 तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें गंगा, यमुना तथा गुप्त सरस्वती के संगम-स्थल पर नहाने के लिए करोड़ों तीर्थ यात्री आते हैं। एनडीएमए ने उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूपीएसडीएमए) के साथ सहयोग से आपातकालीन तैयारी की जांच तथा मोचन प्रक्रमों को मजबूत करने के लिए एक कृत्रिम अभ्यास का संचालन किया।







'आपदा संवाद' ने एनडीएमए के मेजर जनरल वी.के. दत्ता (सेवानिवृत्त) से कुंभ मेला कृत्रिम अभ्यास के बारे में जानने के लिए बात-चीत की

प्र. इस कृत्रिम अभ्यास की खास विशेषताएं क्या थीं ?

उ. सभी तरह के परिदृश्य जो अर्ध-कुंभ के पैमाने वाले मेले में भीड़ के इकट्ठा होने के दौरान घटित हो सकते हैं, का एक के बाद एक संचालित किए गए दो-कृत्रिम अभ्यासों के दौरान अनुकरण (सिमुलेशन) किया गया। पहले अभ्यास का आयोजन दिसंबर, 2018 में किया गया। इससे पूर्व एक समन्वय सम्मेलन आयोजित किया गया जहां हितधारक एजेंसियों ने अपनी योजनाओं को प्रस्तुत किया। इन योजनाओं की लेफ्टिनेंट जनरल एन.सी. मरवाह (सेवानिवृत्त), सदस्य, एनडीएमए द्वारा समीक्षा की गई ताकि अगर कोई कमी है तो उसको सुधारा जा सके।



अनेक स्थानों पर भगदड़ों, एक के कारण मची दूसरी भगदड़ों-का डर, विभिन्न अखाड़ों के पंडाल वाले शिविर क्षेत्रों में आग लगने का खतरा या जहां अंतर्राष्ट्रीय यात्री ठहरे हों, नहाने के दौरान नदी में डूबने की घटना, आंतकवादी हमला, बम या एलपीजी विस्फोट जैसे मुद्दों को ध्यान में रखा गया। सभी मोचन एजेंसियों को इस अभ्यास के संचालन से पूर्व इन मुद्दों के बारे में संतुष्ट किया गया। तथापि, बाद में यह पाया गया कि कुछ एजेंसियां अभ्यास में भाग नहीं ले सकती। इसलिए, राज्य सरकार के अनुरोध पर 11 जनवरी, 2019 को एक और अभ्यास का संचालन किया गया, जिसमें सभी हितधारक एजेंसी ने भाग लिया और प्रथम अभ्यास के बाद किए गए प्रेक्षणों को लागू किया गया। कुछ अतिरिक्त परिदृश्यों को इस उद्देश्य के साथ सभी आपातकालीन सहायता कार्यों (ईएसएफ) का अभ्यास किया गया, ताकि दूसरे अभ्यास के दौरान वे समावेशित किया गया।

परिणामस्वरूप, प्रयागराज में कुंभ मेला अभी तक सफलतापूर्वक चलता रहा है और यह उम्मीद है कि मार्च में मेले की समाप्ति तक यह इसी तरह चलता रहेगा।

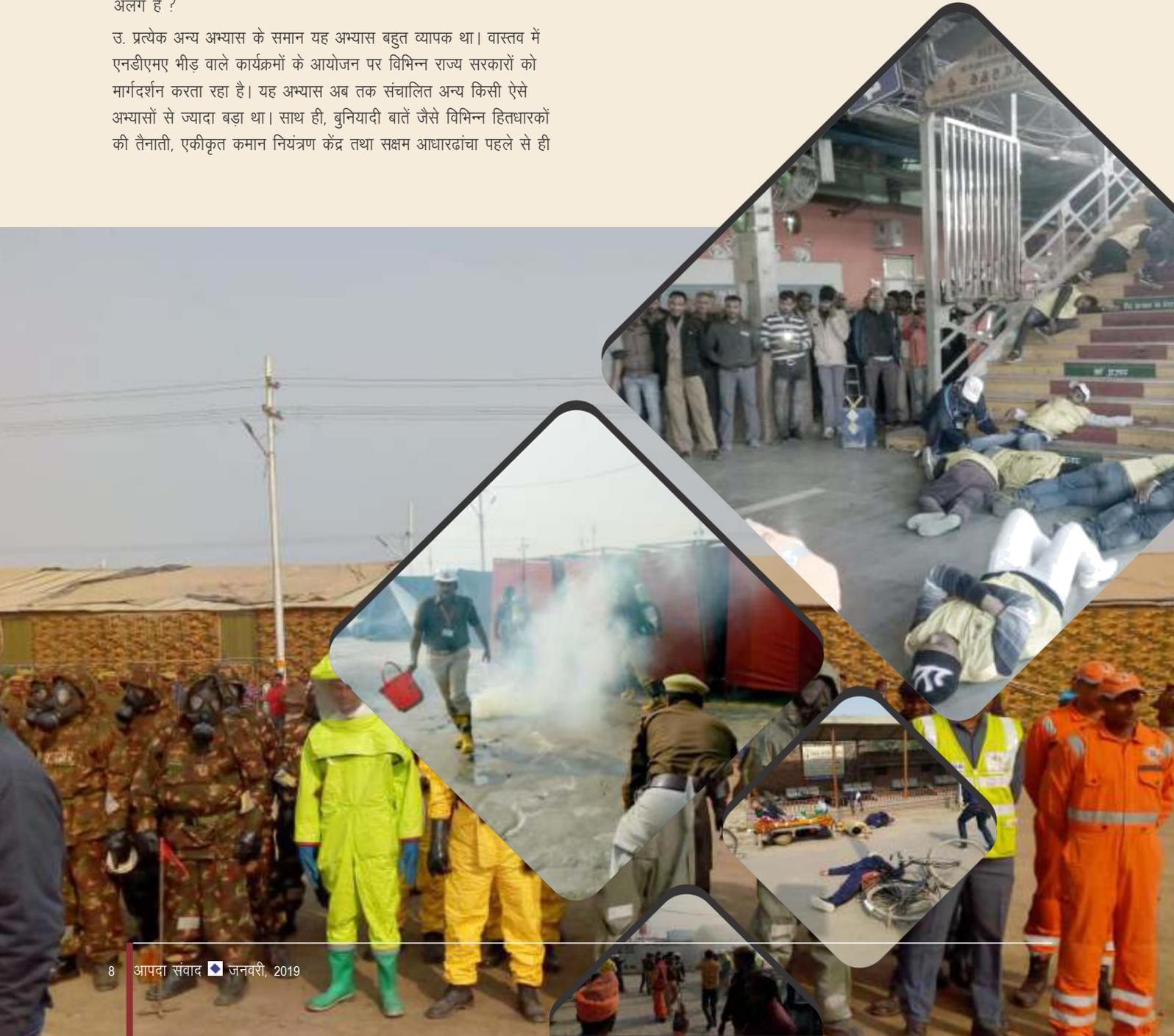
प्र. किसी प्रकार ये अभ्यास पूर्व में किए गए अन्य कुंभ कृत्रिम अभ्यासों से अलग है ?

उ. प्रत्येक अन्य अभ्यास के समान यह अभ्यास बहुत व्यापक था। वास्तव में एनडीएमए भीड़ वाले कार्यक्रमों के आयोजन पर विभिन्न राज्य सरकारों को मार्गदर्शन करता रहा है। यह अभ्यास अब तक संचालित अन्य किसी ऐसे अभ्यासों से ज्यादा बड़ा था। साथ ही, बुनियादी बातें जैसे विभिन्न हितधारकों की तैनाती, एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्र तथा सक्षम आधारठांका पहले से ही

उपलब्ध था। एनडीएमए को कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए एकीकृत कमान, आपदा कमान प्रणाली (आईआरएस), अंतर-एजेंसी समन्वय, संचार प्रणालियों पर मार्गदर्शन देना था।

प्र. कृपया संक्षेप में अभ्यास में एनडीएमए की भूमिका को स्पष्ट करें ?

उ. एनडीएमए ने कुंभ मेले के लगभग सभी पहलुओं-लोगों को रेलवे स्टेशन से लाना, यातायात को संचालित करने के लिए होल्डिंग एरिया का निर्माण, स्नान के क्षेत्रों का प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, सशस्त्र बलों, कुंभ मेला पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल, स्थानीय पुलिस की अखाड़ों के प्रबंधन में भूमिका-पर सभी हितधारकों को उचित मार्गदर्शन दिया है।



14^{वाँ} स्थापना दिवस

आपदाओं हेतु पूर्व चेतावनी



पूर्व चेतावनी आपदा जोखिम न्यूनीकरण का एक प्रमुख तत्व है और इससे लोगों की जान को हाने वाले नुकसान और आर्थिक प्रभागों को न्यूनतम किया जा सकता है। समय पर पूर्व चेतावनी का दिया जाना एक संरचित तथा कुशल मोचन की कुंजी है।

कारगर होने के लिए, पूर्व चेतावनी प्रणालियों को जोखिम में रहने वाले समुदायों को शामिल करने, जन-जागरूकता पैदा करने, चेतावनियों को कारगर ढंग से प्रसारित करने और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आपदा से लड़ने की तैयारी हर समय बनी रहे। पिछले वर्षों के दौरान, भारत ने सटीक तथा समय पर पूर्व चेतावनियों, विशेष रूप से चक्रवात के लिए, जारी करने के काम में उल्लेखनीय प्रगति की है। अभी हाल ही में, प्राधिकरणों में गाजा चक्रवात के पहुंचने से पहले हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल सके। क्योंकि इसके रास्ते के बारे में भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा सटीम पूर्वानुमान लगाया गया था।

इस प्रगति के बावजूद, पूर्व चेतावनी तंत्रों को और बेहतर बनाने के लिए काफी कुछ किया जाना जरूरी है, इसलिए एनडीएमए में 14वें स्थापना दिवस के लिए चुना गया विषय 'आपदाओं हेतु पूर्व चेतावनी' था। स्थापना दिवस को नई दिल्ली में 27 नवंबर, 2018 को मनाया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किरन रिजिजू ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि आपदाओं के प्रति आधी लड़ाई को आपदा के प्रति जागरूकता बढ़ाकर तथा पूर्व चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाकर जीत लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश को और अधिक आपदा समुत्थानशील बनाने में विशेष रूची ले रहे हैं।

हाल की कुछ घटनाओं जहां मछुआरों को पूर्व चेतावनी दिए जाने के बावजूद इस बारे में अनजान पाया गया, की पृष्ठभूमि में मछुआरों तक गहरे समुद्र में चेतावनियों के प्रसार से जुड़े विशेष मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। नाविक सेटलाइट कास्टिलेशन जो मछुआरों के लिए उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में अलर्ट तैयार करते हैं, जैसे विभिन्न प्रौद्योगिकीय उपकरणों की कार्य-प्रणाली पर चर्चा की गई।

आसमानी बिजली तथा आंधी-तूफान के लिए पूर्व चेतावनी के बारे में मुद्दों, राज्य तथा जिला स्तरीय पूर्व चेतावनी कार्य योजनाओं, पूर्व चेतावनी के प्रसार में समुदायों और मीडिया की भूमिका तथा भागीदारी पर भी चर्चा की गई।

एनडीएमए स्थानीय स्तर पर प्राप्त तथा वैध किए गए आंकड़ों के साथ, एक समान, विश्वसनीय तथा एकीकृत राष्ट्रीय-स्तर के डेटाबेस को तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। आपदा समुत्थानशीलता को मजबूत करने के लिए उचित नीतिगत हस्तक्षेप करने के लिए ऐसा किया जाना अनिवार्य है। एनडीएमए ने इस पर सहमति-कार्य को मजबूती देने के लिए स्थापना समारोह के अवसर पर एक प्रस्तुति दी।

हितधारकों ने असुरक्षित समुदायों सहित सभी प्रासंगिक हितधारकों को समयबद्ध तथा सटीक पूर्व चेतावनी जारी करने तथा इसके प्रसार में अपनी कार्ययोजना, भूमिकाओं तथा प्रमुख चुनौतियों पर भी चर्चा की।

आपदा प्रवण क्षेत्र में सब जगह संपर्कता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए, डॉ. पी.के. मिश्रा, प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव ने कहा, 'कोई भी चेतावनी, जितनी भी जल्दी दी जाए, तब तक कारगर नहीं हो सकती जब तक एक सुदृढ़, प्रथम छोर से अंतिम छोर तक पहुंचने वाली, प्रसारण प्रणाली उपलब्ध न हो'।

इस अवसर पर खतरा-रोधी निर्माण के लिए राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण पर एक नियम पुस्तिका और वर्ष 2017 की गुजरात बाढ़ पर एक अध्ययन रिपोर्ट को भी जारी किया गया। प्रशिक्षण नियम पुस्तिका राजमिस्त्रियों को समुत्थानशील तथा मजबूत मकानों का निर्माण करने में समर्थ बनाएगी जिसके कारण किसी आपदा की वजह से लोगों की जान-माल को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। अध्ययन रिपोर्ट में पिछले साल गुजरात में आई बाढ़ के दौरान राज्य द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं तथा सीखे गए सबकों को प्रलेखित किया गया है। यह अध्ययन राज्य की समुत्थानशीलता को और बेहतर बनाने की दिशा में सांस्थानिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए भी सिफारिशें करता है।



एनडीएमए के सदस्यों तथा अधिकारियों, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के मंत्रालय/विभाग से वरिष्ठ अधिकारियों, सिविल सोसायटी तथा एनडीएमए के पूर्व-सदस्य तथा सलाहकार समिति के सदस्य कार्यक्रम में शामिल हुए।

कार्यक्रम में किए गए विचार-विमर्श/चर्चाएं जागरूकता को बढ़ाने और आपदाओं के लिए हमारी पूर्व चेतावनी को बेहतर बनाने में सहायता करने में दीर्घकाल तक काम आएंगें।

तकनीकी सत्र

- आपदाएं तथा पूर्व चेतावनी: परिदृश्य, चुनौतियां तथा आगे का रास्ता
- पूर्व चेतावनी; आसमारी बिजली तथा आंधी और तूफान
- पूर्व चेतावनी में विविध मुद्दे
- आपदा डेटाबेस प्रबंधन •

आपदाओं के प्रति आधी लड़ाई को आपदा के प्रति जागरूकता बढ़ाकर तथा पूर्व चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाकर जीत लिया जाएगा।

आपदा जोखिम प्रबंधन पर आईओआरए समागम



एनडीएमए और गृह मंत्रालय के सहयोग से विदेश मंत्रालय, भारत सरकार आपदा जोखिम प्रबंधन (डीआरएम) पर आईओआरए कलस्टर समूह की एक बैठक का आयोजन कर रहा है जो नई दिल्ली में 05-06 फरवरी, 2019 को आयोजित होगी।

हिंद महासागर के किनारे बसे देशों-रिम एसोसिएशन (आईओआरए) एक अंतर-सरकारी संगठन है और इसके 21 सदस्यों में कई आपदा प्रवण देश शामिल हैं। डीआरएम इसके प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों में से एक है और के आईओआरए देशों में आपदा से लड़ने की क्षमता को अधिक बेहतर बनाने के लिए इसकी कार्य योजना (2017-2021) विशिष्ट लक्ष्य हैं।

दो-दिवसीय बैठक में विचार-विमर्श सत्र आयोजित होंगे और इसका फोकस आईओआरए में डीआरएम के लिए एक प्रारूप कार्य योजना को तैयार करने पर होगा। इसमें कार्य योजना के अंतर्गत सहमत उद्देश्यों पर आगे कार्य करने के लिए एक डीआरएम कोर समूह गठित करने की आवश्यकता पर भी विचार होगा।

इससे प्रभावित देशों में मोचन दलों की तैनाती और राहत सामग्री को एकत्र करने समेत आपदा मोचन मध्यस्थताओं में सहयोग मजबूत होगा। बैठक में किए गए विचार-विमर्शों से सूचना के आदान-प्रदान, आपदा डेटाबेसों की स्थापना और बेहतर प्रथाओं को साझा करने में भी सहायता मिलेगी।

एससीओ संयुक्त अभ्यास 2019

शहरी भूकंप खोज एवं बचाव पर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के एक संयुक्त अभ्यास का नई दिल्ली में 21-24 फरवरी, 2019 के दौरान आयोजन किया जाएगा। चार-दिवसीय अभ्यास का राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) द्वारा आयोजन किया जाएगा। यह अभ्यास आईएनएसएआरएजी (अंतर्राष्ट्रीय खोज तथा बचाव समूह) जो शहरी खोज तथा बचाव और प्रचालनात्मक क्षेत्र समन्वय हेतु प्रतिबद्ध आपदा-प्रवण और आपदा-मोचन करने वाले देशों तथा संगठनों का एक नेटवर्क है, के दिशानिर्देशों पर आधारित होगा।

सभी 08 सदस्य देशों-भारत, कजाकिस्तान, चीन, किरगिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उजबेकिस्तान-से प्रतिनिधि अभ्यास में भाग लें।

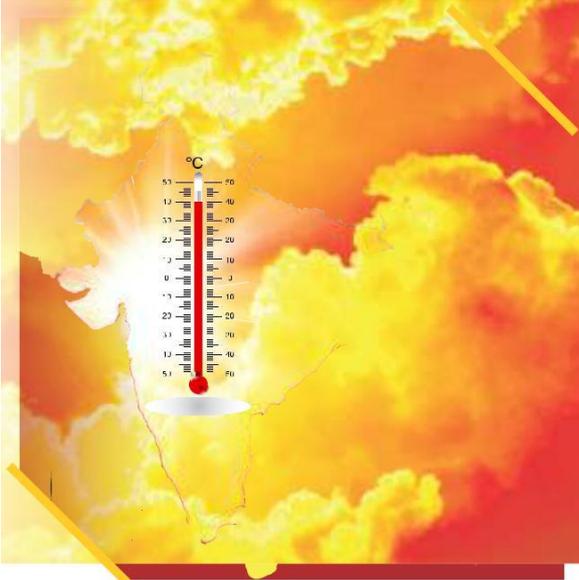
यह अभ्यास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मोचन तथा अंतर्राष्ट्रीय की सहायता वाले एक बड़े भूकंप परिदृश्य में समन्वय प्रोटोकॉलों तथा प्रक्रियाओं की प्रैक्टिस करने तथा उसको सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करेगा। यह अभ्यास किसी आपदा का मोचन करते समय विभिन्न चुनौतियों के समाधान हेतु बेहतर प्रथाओं को साझा करने के लिए और सदस्य देशों की आपदा से निपटने की तैयारी तथा समुत्थानशीलता की परीक्षा लेने का अवसर भी प्रदान करेगा।

अगस्त, 2017 में किरगिस्तान में चोलपोन आटा में आपातकालीन स्थितियों की रोकथाम तथा उनके प्रबंधन से निपटने हेतु एससीओ की सरकारों के प्रमुख की नौवीं बैठक में देश की तरफ से संबोधित करते हुए, केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने प्राकृतिक आपदाओं से बेहतर ढंग से निपटने के लिए एक भूकंप बचाव अभ्यास की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा। अभ्यास के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक दो-दिवसीय प्रारंभिक बैठक का एनडीआरएफ द्वारा नवंबर, 2018 में नई दिल्ली में भी आयोजन किया गया। प्रारंभिक बैठक के दौरान कार्यक्रमों की किस्में, तौर-तरीकों, स्थलों, प्रोटोकॉल तथा जरूरतों पर मुख्य अभ्यास के सुचारु संचालन हेतु काम किया गया।

एक आपस में जुड़े हुए संसार में, जहां संसार के एक भाग के हुई कार्रवाईयों से संसार के दूसरे भागों में जोखिम उत्पन्न होते हैं, यह अनिवार्य है कि एससीओ देश अपने आपदा जोखिमों को कम करने के लिए एक-साथ आएँ। यह अभ्यास क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करेगा और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को एक अतिरिक्त गति प्रदान करेगा।



लू (ग्रीष्म लहर) पर कार्यशाला



महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से लू-2019 के प्रति तैयारी, प्रशमन तथा प्रबंधन पर नागपुर में 27-28 फरवरी, 2019 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा।

लू हाल के वर्षों में विश्व में बड़ी विकट मौसमी घटनाओं में से एक विकट घटना के रूप में उभरी है। जलवायु परिवर्तन भारत में तापमान को अधिक डिग्री तक बढ़ाने के साथ-साथ लू की आवृत्ति तथा विकटता को बढ़ा रहा है।

एनडीएमए ने 2016 में 'लू की रोकथाम तथा प्रबंधन-कार्ययोजना की तैयारी हेतु दिशानिर्देश' को सूत्रबद्ध किया तथा सभी राज्यों को परिचालित किया। दिशानिर्देशों ने चरम ग्रीष्म लहर (लू) के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा कार्यकलापों के क्रियान्वयन, समन्वयन तथा मूल्यांकन हेतु एक रूपरेखा प्रदान की है। दिशानिर्देशों को 2017 में और संशोधित किया गया। सभी हितधारकों द्वारा की गई निकट तथा सतत मॉनीटरिंग के साथ इसके कारगर क्रियान्वयन से 2016, 2017 और 2018 में लू से होने वाली मौतों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई।

कार्य योजनाओं की तैयारी क्रियान्वयन में सहायता देने के अलावा, कार्यशाला का उद्देश्य ठंडी छतों की प्रौद्योगिकी का अनुकूलन, 1 कवरेज और हरित क्षेत्रों को बढ़ाना ताकि लू और जलवायु परिवर्तन असुरों के जोखिम को कम किया जा सके, जैसे दीर्घावधिक उपायों सहित विभिन्न विकासात्मक योजना के एकीकरण के बारे में चर्चा करना भी है।

आपदा समुत्थानशील आधारढांचा पर कार्यशाला

संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (यूएनआईएसडीआर) के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एडीएमए), भारत नई दिल्ली ने 19-20 मार्च 2019 के दौरान "आपदा समुत्थानशील आधारढांचा" पर दूसरी अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। कार्यशाला में भागीदार देशों से प्रतिनिधि एक साथ इकट्ठे होंगे जिनमें उनकी आपदा जोखिम प्रबंधन एजेंसी, प्रमुख आधारढांचा क्षेत्र, बहुपक्षीय विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, अकादमियों, वैज्ञानिक संस्थाएं, निजी क्षेत्र तथा नीतिगत थिक टैंकों का प्रतिनिधित्व होगा। सभी तरह की हानि में कमी लाने के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भागीदार देशों की अपनी आपदा जोखिम प्रबंधन एजेंसियों के प्रतिनिधियों को यह कार्यशाला एक मंच पर इकट्ठा करेगी।

सेन्डाई रूपरेखा में तय किए गए सभी आपदा समुत्थानशील आधारढांचा में निवेश अनिवार्य है। पिछले दो सालों के दौरान भारत जी-20 शिखर सम्मेलनों और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रालयीन सम्मेलन (एएमसीडीआरआर) समेत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर "आपदा समुत्थानशील आधारढांचा गठबंधन (सीडीआरआई)" की वकालत करता रहा है। सीडीआरआई की अंतर-देशीय ज्ञान विनिमय तथा क्षमता विकास भागीदारी के रूप में कल्पना की गई है।

यह कार्यशाला आधारढांचा की आपदा समुत्थानशीलता निर्माण के एक प्रभावी लिखत के रूप में अंतर-देशीय ज्ञान भागीदारी के आयामों पर विचार होगा। इस कार्यशाला में भागीदार देशों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ ज्ञान विनिमय सुकर बनाने के लिए आधारढांचा परिसम्पत्तियों, डाटा मानकीकरण को अपग्रेड करने के लिए उनके क्षमता विकास हेतु ठोस कार्य योजनाओं पर भी दृष्टि डाली जाएगी।

जनवरी, 2018 में, आपदा समुत्थानशील आधारढांचा पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का नई दिल्ली में आयोजन किया गया।



शीत लहर से कैसे बचें

निम्नलिखित सरल उपायों का पालन करें

- सर्दी के मौसम वाले पर्याप्त कपड़े पहनें
- आम दस्तानों (ग्लावर) के स्थान पर विशेष प्रकार के दस्तानों (मिटन) को पहनने के लिए चुनें
- जितना संभव हो, घर के अंदर या कार्यालय के अंदर रहें
- नियमित रूप से गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें
- बुजुर्ग तथा बच्चों का ध्यान रखें
- पर्याप्त पानी का भंडार रखें क्योंकि पाइपों में पानी जम सकता है
- आपातकालीन आपूर्तियों के सामान को तैयार रखें
- मौसम के ताजा हाल के लिए रेडियो सुने, टीवी देखें, अखबारों को पढ़ें



पता:

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)

ए-1, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली-110029.

दूरभाष संख्या : +91-11-26701700

नियंत्रण कक्ष : +91-11-26701728

हेल्पलाइन संख्या : 011-1078

फैक्स : +91-11-26701729